AADHAAR

PRABHAT KHABAR, Ranchi, 7.9.2017
Page No. 8, Size:(33.11)cms X (26.75)cms.

तीन साल में विभिन्न पेंशन योजनाओं में तीन लाख फर्जी लाभुक पकड़े गये

वरीय संवाददाता ▸ रांची

- आधार से जोड़ने तथा लाभुकों को सीधे उनके खाते में भुगतान से फर्जीवाड़ा पकड़ा गया
- कल्याण सह समाज कल्याण मंत्री व समाज कल्याण सचिव ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी
- मंत्री व सचिव सूचना भवन में सरकार के 1000 दिन की उपलब्धि बता रहे थे

समाज कल्याण विभाग ने गत तीन वर्षों में विभिन्न पेंशन के तीन लाख फर्जी लाभुक पकड़े हैं. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के इन फर्जी लाभुकों को सूची से हटाने के बाद राज्य सरकार को करीब 180 करोड़ रुपये की सालाना बचत हो रही है. विभाग पेंशन योजना पर सालाना 1300 करोड़ रुपये खर्च करता है. दरअसल पेंशन भुगतान को आधार से जोड़ने तथा लाभुकों को सीधे उनके खाते में भुगतान (डीबीटी) से यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है. कल्याण सह समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडो व समाज कल्याण सचिव मुखमीत सिंह भाटिया ने बुधवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी. मंत्री व सचिव सूचना भवन में सरकार के 1000 दिन को उपलब्धि बता रहे थे.

सचिव ने कहा कि तकनीक के माध्यम से पेंशन योजना में न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि इससे भुगतान में तेजी आयी है तथा पूरे सिस्टम को मॉनिटरिंग संभव है. अब हर महीने को पांच तारीख तक पिछले माह की पेंशन राशि का भुगतान हो जाता है. मंत्री ने कहा कि 34 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति तथा करीब 11 लाख को साइकिल योजना का लाभ मिल रहा है. विभाग अपने आवासीय विद्यालयों की संख्या भी 132 से बढ़ा कर 143 तथा आश्रम व एकलव्य विद्यालयों की संख्या सात से बढ़ा कर 47 करने जा रहा है. सचिव श्री भाटिया ने कहा कि प्ले स्कूल के लिए नियमावली बनाने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है. कुपोषण के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि इस समस्या से हमें मिल कर निबटना होगा. इसमें समाज व मीडिया की भी अहम भूमिका है. विभाग जल्द ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए अंडा उपलब्ध करायेगा. विभाग के संयुक्त सचिव ने बाल संरक्षण के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी. मौके पर कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव राम प्रवेश प्रसाद व समाज कल्याण निदेशक राजीव रंजन भी मौजूद थे.

संवाददाता सम्मेलन में मंत्री लुईस मरांडी व विभाग के वरीय अधिकारी.

विभाग की उपलब्धियां

- पीड़ित महिलाओं के लिए रांची, जमशेदपुर व धनबाद में वन स्टॉप सेंटर शुरू
- ट्रैफिकिंग से मुक्त बच्चों व महिलाओं के लिए दिल्ली व रांची में पुनर्वास केंद्र
- देवघर में लड़कियों के लिए चिल्ड्रेन व ऑब्जर्वेशन होम तथा पुनर्वास हॉल का निर्माण कार्य शुरू किया गया
- कुपोषण मुक्ति के लिए राज्य पोषण मिशन की शुरुआत
- कुपोषण से ज्यादा प्रभावित छह जिलों में 10388 अतिरिक्त सेविका सह पोषण सखी की नियुक्ति
- एचआइवी पीड़ित व आदिम जनजातियों को 600 रुपये प्रति माह पेंशन
- देवघर, गढ़वा व गोड्डा में ओल्ड एज होम बनाया गया
- आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 12593 वाटर प्यूरीफायर दिये गये, शेष के लिए प्रक्रिया जारी

कल्याण विभाग की उपलब्धियां/कार्यक्रम

- आवासीय विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल सुधारा गया. सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम लागू
- 13 अनुसूचित जिलों के 30 प्रखंडों के 1254 गांव में आजीविका व आय वृद्धि कार्यक्रम, इसी के तहत 135 एकड़ में आम के पौधे लगे
- दुमका व पश्चिम सिंहभूम के दो-दो प्रखंड के दो हजार बीपीएल परिवार दो साल में एपीएल बनेंगे
- गत एक हजार दिन में 41398 लोगों को वन भूमि का पट्टा मिला (2015-16 तक 18943 लोगों को)
- आवासीय विद्यालयों में पठन-पाठन सहित अन्य मद में प्रति छात्र राशि 14590 से बढ़ा कर 32410 रुपये की गयी
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत 1200 गांव के 11 हजार लाभार्थी व 2200 महिला एसएचजी को मिल रहा लाभ
- कुल 1757 सरना, मसना, जाहेर स्थान व हड़गड़ी की घेराबंदी की जा रही है.
- शहीद ग्राम विकास योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान